सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

नई दिल्ली, 03 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को दिसम्बर, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधुरी)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली के सभी सदस्य।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. वित्त राज्य मंत्री के प्रधान सचिव, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (आ.का.) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।
11. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.।
12. अपर सचिव (श्री ए.गिरिधर) मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. सुश्री मीरा स्वरूप, विशेष सचिव (वित्त)।
14. श्री ए.एम. बजाज, अपर सचिव (एफएम), आ.का.वि.
15. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव (बजट), आ.का.वि.।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आ.का.वि.
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।

    वरिष्ठ सलाहकार (सीएवंसी/एफएसएलआर/एफएस और सीएस)/ संयुक्त सचिव (बीसी एवं आईईआर)/ संयुक्त सचिव (निवेश)/ संयुक्त सचिव(सीएवंसी)/ संयुक्त सचिव(आइपीपी)/(आईएसडी)/ सलाहकार (आईईआर)/ सलाहकार (बीसी)/ सलाहकार(प्रशा)/

सलाहकार(निवेश)/ सलाहकार(आर्थिक प्रभाग)/ सलाहकार(आईईआर)/ सलाहकार(आइपीपी)/सीएएए।

18. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एवं सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
19. गार्ड फाइल – 2021

सं. ए-45011/4/2021-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

***

विषयः दिसंबर, 2021 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. वृहत्-आर्थिक अवलोकन

वित्त वर्ष की चालू तिमाही में भारत के आर्थिक सुधार में मजबूती आने की उम्मीद है, जैसा कि 2019 के इन्ही महीनों में उच्च आवृति संकेतकों (एचएफआई) का महामारी से पूर्व के अपने स्तर को पार करने से स्पष्ट है। प्रमुख बहुपक्षीय और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भारत से 2021 (वित्त वर्ष 21-22) में 8% -10% के बीच बढ़ने की अपेक्षा करती है और सरकार ऐसा करती भी है। आईएमएफ ने प्रमुख देशों में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि, राज्यों में ओमीक्रोन के मामलों में वृद्धि आर्थिक सुधार के लिए एक जोखिम है। क्षेत्रवार वृद्धि दर **अनुबंध** में दी गई है।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दो अधिसूचनाएं जारी की गईं (i) 'बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध', 'अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन डिपॉजिटरी रसीद' को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित करते हुए जारी करने हेतु सक्षम बनाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कारोबार करना और (ii) 'इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद' को प्रतिभूतियों के रूप में घोषित करना।

(ii) एक्जिम बैंक के माध्यम से किर्गिस्तान सरकार को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान की गई।

(iii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) यूरोपीय निवेश बैंक से आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 250 मिलियन यूरो का ऋण;

(ख) केएफडब्ल्यू से सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो का ऋण;

(ग) केएफडब्ल्यू से ऊर्जा सुधार कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के लिए 140 मिलियन यूरो का ऋण और 2 मिलियन यूरो का अनुदान;

(घ) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से उत्तराखंड एकीकृत और लचीला शहरी विकास परियोजना (किश्त 1) के लिए 125 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(ङ) एडीबी से तमिलनाडु परियोजना में शहरी गरीब क्षेत्र की परियोजना के लिए समावेशी, लचीला और सतत आवास के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(च) एडीबी से सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम (किश्त 1) परियोजना के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(छ) एडीबी से असम कौशल विश्वविद्यालय परियोजना के लिए 112 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण;

(ज) चेन्नई सिटी पार्टनरशिप के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण: विश्व बैंक से सतत शहरी सेवा कार्यक्रम;

(झ) विश्व बैंक से शिमला-हिमाचल प्रदेश जल आपूर्ति और सीवेज सेवा सुधार कार्यक्रम के लिए 160 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।

(ञ) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 80 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर हस्ताक्षर किए गए; तथा

(ट) विश्व बैंक से समावेशी सामाजिक सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल राज्य क्षमता निर्माण के लिए 125 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण।

3. दिसम्बर, 2021 माह के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं:

i. वेंचर कैपिटल और निजी इक्विटी निधि का प्रतिनिधित्व करने वाले निवेशकों के चयनित समूह के साथ माननीय प्रधान मंत्री की एक गोलमेज वार्ता आयोजित की गई।

ii. पहली जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुखों की बैठक के साथ-साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें माननीय वित्त मंत्री ने इंडोनेशिया की प्रेसीडेंसी के अंतर्गत जी-20 के वर्तमान विषय पर एक उच्च स्तरीय चर्चा में भाग लिया: "एक साथ स्वस्थ हों, मजबूत हों"

iii. माननीय वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक सुश्री गीता गोपीनाथ से उनकी भारत यात्रा के दौरान मुलाकात की तथा अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

iv. 106वीं पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) बैठक के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर हाइब्रिड-डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी) मॉडल पर पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के सोननगर-गोमोह खंड (261.3581 किलोमीटर) के विकास के प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी।

v. 107वीं पीपीपीएसी बैठक के दौरान पीपीपी के माध्यम से भारत नेट के विकास (सृजन, उन्नयन, संचालन, अनुरक्षण और उपयोग) के प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी।

vi. 39वीं कार्यकारी समिति की बैठक के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा पीपीपी मोड पर डीबीएफओटी (डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और अंतरण) के आधार पर कैमूर और बक्सर (बिहार) में खाद्यान्न साइलो के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन सहायता को अंतिम अनुमोदन दिया गया था।

vii. अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ-20 पुनःपूर्ति की चौथी बैठक आभासी रूप से विश्व बैंक ईडी (भारत) के साथ आयोजित की गई थी।

viii. आर्थिक कार्य विभाग जांच समिति की 123वीं बैठक के दौरान बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार किया गया।

ix. विभिन्न नीति समीक्षा और निवेश कार्यों पर विचार करने के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई थी और भारत गुजरात शिक्षा अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर को अनुमोदन दिया गया था।

x. विभिन्न नीति समीक्षा और निवेश कार्यों पर विचार करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई थी।

xi. इंडोनेशियाई प्रेसीडेंसी के अधीन पहली जी-20 वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुखों की बैठक बाली में आयोजित की गई थी।

xii. निवेश अध्याय पर दूसरे दौर की वार्ता प्रस्तावित भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के अंतर्गत आयोजित की गई थी।

xiii. वित्तीय स्थिरता बोर्ड की मानक कार्यान्वयन पर स्थायी समिति (एससीएसआई) की बैठक एससीएसआई कार्य योजना, विषयगत सहकर्मी समीक्षा और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान सुधारों की निगरानी पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

xiv. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए), विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डेडीकेटेट फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के तहत एमआईजीए गारंटी के लिए वचनबद्धता की रूपरेखा पर चर्चा की गई।

xv. माह के दौरान राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष न्यासी लिमिटेड (एनआईआईएफटीएल) की वार्षिक सामान्य बैठक तथा एनआईआईएफटीएल तथा राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड की बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं।

xvi. म्यांमार के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर चर्चा का एक समन्वेशी (प्रथम) दौर आयोजित किया गया था।

xvii. उज्बेकिस्तान के साथ बीआईटी पर चौथे दौर की वार्ता हुई।

4. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन

विशेषकर सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना

शून्य

6. विभाग में माह के दौरान अनुमोदित एफडीआई प्रस्तावों और विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षारत एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

विभाग में अनुमोदन हेतु प्रतीक्षा: 12

7. सरकार में निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने के लिए सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति:

i. प्रस्तुत करने के माध्यमों की समीक्षा की गई है और परिवर्तन लागू किए जा रहे हैं।

ii. विभिन्न स्तरों पर स्टाफ की कमी के चलते कई अधिकारी डेस्क ऑफिसर पैटर्न पर काम कर रहे हैं।

iii. आर्थिक कार्य विभाग में ई-ऑफिस संस्करण 7.0 लागू किया गया है।

iv. लंबित मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

v. कई आईटी उपकरण और आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग/कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे विभाग में दक्षता बढ़ रही है। विभाग में 90% ई-फाइल है।

***

अनुबंध

तालिका 1: सकल घरेलू उत्पाद और उसके घटकों के मांग पक्ष में वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)			
घटक	2020-21 की दूसरी तिमाही की तुलना में संवृद्धि	**2021-22** की पहली तिमाही की तुलना में	**2019-20** की पहली छमाही में वसूली
कुल खपत	8.6	4.8	92.7
सरकारी खपत	8.7	(-) 14.2	94.7
निजी खपत	8.6	9.2	92.3
कुल निश्चित पूंजी निर्माण	11.0	11.8	91.8
स्टॉक में बदलाव	2.7	7.8	102.1
कीमती सामान	183.3	603.6	155.1
निर्यात	19.6	8.4	113.0
आयात	40.6	16.8	104.8
सकल घरेलू उत्पाद	**8.4**	**10.4**	**95.6**
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			

तालिका 2: आपूर्ति पक्ष पर जीवीए और उसके घटकों की वास्तविक वृद्धि (प्रतिशत)			
क्षेत्र	2020-21 की दूसरी तिमाही की तुलना में	**2021-22** की पहली तिमाही की	**2019-20** की पहली छमाही में
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	**4.5**	(-) 16.2	**108.0**
उद्योग	**6.9**	**5.9**	98.6
खनन और उत्खनन	15.4	(-) 14.0	102.5
उत्पादन	5.5	7.9	99.9
बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	8.9	5.2	107.2
निर्माण	7.5	8.7	92.1
सेवाएं	**10.2**	**16.2**	**92.6**
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	8.2	24.9	80.1
वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	7.8	7.0	98.2
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	17.4	24.7	101.1
मूल कीमतों पर जीवीए	**8.5**	**7.9**	96.3
स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			

तालिका 3: मुद्रास्फीति - सीपीआई-सी, डब्ल्यूपीआई (प्रतिशत में)			
	नवंबर 2020	**अक्टूबर 2021**	**नवंबर 2021**
सीपीआई-सी	6.93	4.48	4.91
डब्ल्यूपीआई	2.29	12.54	14.23
स्रोत: सीपीआई-सी और ओईए के लिए एनएसओ, डब्ल्यूपीआई के लिए डीपीआईआईटी नोट: पिछले दो महीनों के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति और पिछले एक महीने के लिए सीपीआई-सी मुद्रास्फीति			

तालिका 4: मौद्रिक विकास	
मद	**17.12.2021**
पॉलिसी रेपो रेट	4.0
10-वर्ष जी-सेक पार यील्ड (एफबीआईएल)	6.45
बैंक ऋण वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि #	7.3
नोट: # 03.12.2021 तक	

तालिका 5: पण्य व्यापार प्रदर्शन (सीमा शुल्क के आधार पर) (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)			
	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
नवंबर 2020	23.6	33.8	(-) 10.2
नवंबर 2021	30.0	52.9	(-) 22.9

तालिका 6: सेवा व्यापार प्रदर्शन (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)			
अक्टूबर 2021	19.9	11.6	8.2
स्रोत: वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.12.2021 के अनुसार अनंतिम डेटा।			

तालिका 7: भुगतान संतुलन		
मद	**2020-21 (अप्रैल-सितंबर)**	**2021-22 (अप्रैल-सितंबर) (पी)**
चालू खाता शेष (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	34.4	(-) 3.0
चालू खाता शेष/जीडीपी (प्रतिशत)	3.0	(-) 0.2
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक		

तालिका 8: विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
मार्च-अंत, 2021	577.0
24.12.2021	635.1